22 AUG 2019

डेली न्यूज, जयपुर

नौ महीने बाद भी सहकारी बैंकों की वित्तीय हालत बेपटरी

कर्ज माफी के बाद वित्तीय हालात हुए बदतर

55 हजार किसानों ने करवाया पंजीयन, 36 हजार को मिला लोन

वर्तमान में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन ऋण पोर्टल पर सीकर के 55 हजार किसानों ने पंजीयन करवाया है, लेकिन 36 हजार किसान ही लाभान्वित हो पाए हैं। पंजीयन के बाद किसानों को ऋण तो स्वीकृत हो गया है, लेकिन बैंक के पास देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। ऐसे में स्वीकृत ऋण भी किसानों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। किसान उलझन में है कि कर्ज मिलेगा तो कैसे।

डेली न्यूज

सीकर ▷ 21 अगस्त

प्रदेश में छह माह के दौरान दो बार कर्ज माफी की घोषणा ने सहकारी बैंकों की व्यवस्था बेपटरी कर दी है। नई सरकार के गठन के बाद भी सहकारी बैंकों के पास पुनर्भरण राशि नहीं पहुंच पाई है। जिसका नतीजा है कि प्रदेश में अधिकांश जगह खरीफ की बुआई हो चुकी है, लेकिन बैंकों के पास ऋण माफी का प्रमाण पत्र ले चुके किसानों को ब्याजमुक्त ऋण बांटने के लिए पैसे तक नहीं हैं। ऐसे में किसानों को बैंक और सहकारी समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मई में वसुंधरा सरकार ने सहकारी बैंकों से किसानों का 50 हजार तक ऋण माफ किया था। इसके बाद कांग्रेस ने चुनावी कर्जमाफी का चुनाव वादा कर विधानसभा में सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव आ जाने से आनन-फानन में सहकारी बैंकों से लिया 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ कर प्रमाण पत्र बांट दिए।

ऋण ज्यादा, स्वीकृति कम

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने जुलाई, 2018 तक 200 करोड़ का ऋण बांट दिया था, जबकि इस बार अगस्त बीतने को है, लेकिन अब तक महज 117 करोड़ के ऋण की स्वीकृति ही जारी की गई है।

सीकर प्रदेश में दूसरे पायदान पर

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रदेश दूसरी ऐसी बैंक है जो हर साल खरीफ और रबी सीजन में लाखों किसानों को ऋण दे रही है। वर्तमान में यह हालत है कि मौजूदा सरकार ने वोट की राजनीति के लिए कर्जमाफी कर बैंकों से प्रमाण पत्र तो बंटवा दिए, लेकिन बैंकों को कर्जमाफी का एक रुपया भी नहीं दिया।